मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

कमांक:387/1188/2018/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक22/05/2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः–. सहायक अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में ।

संदर्भः– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का पत्र कमांक/TM/07/GIA/D-251, दिनांक 07–05–2019 ।

–::000::–

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,मध्यप्रदेश,ग्वालियर द्वारा पत्र में सहायक अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार एवं मुख्य शीर्षवार सूची उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु संलग्न है। पत्र में दिये गये लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कर महालेखाकार एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

15/19

(तेजस्वी एस नायक)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा0कमांक:388/1188/2018/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक22/05/2019

प्रतिलिपिः

1/ प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,मध्यप्रदेश,ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

No./TM/07/GIA/ D-251

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of The Principal Accountant General (A & E) - I
Madhya Pradesh, Gwalior

सत्यमेव जयते

To,

The Principal Secretary (Finance)
Government of Madhya Pradesh,
Finance Department,
Vallabh Bhawan,
Bhopal-462004

दिनांक / Date : 7/5/2019

Subject: Outstanding Utilisation Certificates (UCs) against Grants-in-aid sanctioned by the State Government

Reference: No/TM07/GIA/ D-2122 Date 31.1.2019

Sir,

Kindly refer to Rule 182 of Madhya Pradesh Financial Code, a formal Utilisation Certificate (UC) about the proper utilisation of the conditional grant is to be furnished to the Principal Accountant General (A&E) by the sanctioning authority on or before 30th September of the year following that to which the Grant is related.

It is noticed that sanctions of Grant-in-aid (GIA) received from departments do not specifically indicate whether grant is conditional or unconditional and therefore the possibility of booking of unconditional grants under conditional grants cannot be ruled out. The status of outstanding UCs is given below:

Year	No. of UCs awaited	Amount (in crore)
Up to 2013-14	20070	14956.32
2014-15	2	401.49
2015-16	9	39.18
2016-17	2	5.15
2017-18	0	0
2018-19 (upto Feb. 2019)	16	471.59
Total	20099	15873.73

The fact of proper utilisation of funds could not be ascertained because of non-receipt of Utilisation Certificates from the users. Maximum number of UCs have become pending. Separate vouchers codes may be allotted to conditional grants and unconditional grants by the treasuries while booking the amount under GIA vouchers so that proper mapping of data may be done between treasury and AG Office. It is also noticed that data received from treasuries are booked under single code (42-007) due to which proper mapping could not be done in this office. Individual voucher codes for GIA has been allotted in VLC system by this office to segregate conditional and unconditional grants as 104 for conditional grants and 160 for unconditional grants.

The amount booked under GIA in conditional grants require utilisation certificates to be produced for Audit. Department wise details of outstanding utilisation certificates as on February 2019 is enclosed. Hence, you may direct the concerned authorities to provide outstanding utilization certificates or to specify the Grant-in-Aid which are unconditional that do not require utilization certificates.

Enclosure: As above

Yours Sincerely,

Pr. Accountant General

'लेखा भवन', झांसी रोड, ग्वालियर - 474 002
"Lekha Bhawan", Jhansi Road, Gwalior - 474 002
Telephones : 0751-2372021, 2426452, 2322400, Fax : 0751-2378462
E-mail : agaeMadhyapradesh1@cag.gov.in

Department wise position of Pending Utilisation Certificates as on February 2019

Sl.No.	Major Head	Description	No. of UCs	Amount in Rs. (Crore)
1	3604	स्थनीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन	1268	8711.00
2	2408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1153	2186.8
3	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1021.62
4	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1143	748.03
5	2401	फसल कृषि-कर्म	3090	439.99
6	2217	शहरी विकास	684	321.34
7	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गो का कल्याण	79	306.42
8	2425	सहकारिता	706	268.68
9	2216		5	324.21
10	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
11	2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	657	217.45
12	2403	पशुपालन	495	201.86
13	2852	उद्योग	2987	187.07
14	2505	ग्राम रोजगार	42	290.62
15	2052	सचिवालय-सामान्य सेवांए	93	87.72
16	2236	पोषण	9	86.65
17	3452	पर्यटन	185	81.05
18	2230	श्रम तथा रोजगार	1269	44.61
19	2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	28	23.36
20	2250	अन्य सामाजिक सेवांए	6	22.94
21	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
22	2702	लघु सिंचाई	280	12.55

23	2405	मछली पालन	3385	10.52
24	2204	खेलकूद तथा युवा सेवांए	5	10.78
25	2075	विविध सामान्य सेवांए	532	4.95
26	2055	पुलिस	12	1.76
27	2014	न्याय प्रशासन	375	1.55
28	2220	सूचना तथा प्रचार	35	1.50
29	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	30	1.29
30	4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
31	2029	भू राजस्व	104	1.20
32	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4	0.17
33	2205	कला तथा संस्कृति	1	0.15
34	2047	अन्य राजकोषीय सेवांए	4	0.01
		योग	20099	15873.73

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/टी.एम.